तैयारी | एक ही जगह पर उपलब्ध होगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षा की सुविधा, 103 एकड़ क्षेत्रफल में होगा विकास

मोहान रोड पर दुबई, कतर जैसी बनेगी एजुकेशन सिटी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। मोहान रोड योजना में दुबई और कतर जैसे देशों की तर्ज पर एजूकेशन सिटी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार और अन्य विशेषज्ञों की राय से एजूकेशन सिटी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनेगी। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत योजना में विशेष शैक्षिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। दुबई व कतर देशों की तर्ज पर एक ही जगह पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पारिजात सभागार में योजना के सम्बंध में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में इसका खाका खींचा गया। बैठक में मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार केवी राजू, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार व प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल व एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने विचार विमर्श किया। बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष ने योजना के ले-आउट का प्रेजेन्टेशन दिया गया। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ पंचकुला की तरह मोहान रोड योजना का विकास ग्रिड पैटर्न पर किया जाएगा। योजना में कुल 08 सेक्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शॉपिंग सेंटर, बारात घर और वेन्डिग जोन का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही सभी बड़े चौराहों पर रोटरी विकसित की जाएगी। बायीं ओर मुड़ने वाले ट्रैफिक को फ्री-पास दिया जाएगा। योजना में 112.50 वर्गमीटर से 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 2532 आवासीय भूखण्ड के साथ ग्रुप हाउसिंग के बड़े भूखण्ड होंगे। योजना में शिक्षण संस्थानों के लिए भूखण्ड नियोजित करते एजुकेशन सिटी का स्वरूप दिया जाएगा। दुबई, कतर में एजुकेशन सिटी के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी।

25 %भुगतान पर कब्जा व लीज रेंटल प्लान आदि का विकल्प भी दिया जाएगा

60 मीटर और 45 मीटर चौड़ी रोड पर विकसित की जाएगी एजुकेशनल सिटी

बड़ा भूखंड खरीदने के लिए मिलेंगे विकल्प

विश्वविद्यालयों व शिक्षा क्षेत्र के निवेशकों को इतना बड़ा भूखण्ड खरीदने व इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में आर्थिक बाधा न आए। इसके लिए कई विकल्प दिये जाएंगे। जैसे, खरीददारों को 25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा व लीज रेंटल प्लान आदि का आकर्षक विकल्प दिया जाएगा। इसमें कोई मास्टर डेवेलपर चाहे तो वह अकेले ही भूखण्ड खरीदकर विकास कार्य करा सकेगा।